Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 1, 2016 (CHAITRA 12, 1938 SAKA)

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2016

सं0एच0वी0एस0–एल0ए0–35/2016/23.— हरियाणा के राज्यपाल का दिनांक 31 मार्च, 2016 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता हैः–

"मैं, प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल, हरियाणा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उप खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा हरियाणा विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 31 मार्च, 2016.

प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।"।

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st April, 2016

No. HVS-LA-35/2016/23.— The following order by the Governor of Haryana dated the 31 st March, 2016 is published for general information :-

"I PROF. KAPTAN SINGH SOLANKI, GOVERNOR OF HARYANA IN EXERCISE OF THE POWERS CONFERRED UPON ME BY VIRTUE OF SUB-CLAUSE (a) OF CLAUSE (2) OF ARTICLE 174 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, DO HEREBY PROROGUE THE HARYANA VIDHAN SABHA.

CHANDIGARH:
THE 31ST MARCH, 2016

PROF. KAPTAN SINGH SOLANKI,
GOVERNOR OF HARYANA.".

R. K. NANDAL,
Secretary.

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. 5/4/2002-1AR.— In exercise to the powers conferred by Sub-section (3) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) and all other powers enbling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby, on the recommendation of the Committee as specified in the above said Sub-section appoints the following as State Information Commissioner, Haryana with effect from the date of their joining as such:-

1. Sh. Bhupender Kumar Dharmani
2. Sh. Sukhbir Singh Gulia

The terms and conditions of their appointment will be issued separately.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 9/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 59/2016.— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 14/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 59/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 के प्रतिनिर्देश से मैं, श्यामल मिश्रा, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वितायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2016, से लागू होंगे।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, तालिका में, शीर्ष ''II–देशी स्पिरिट'' शीर्ष के नीचे श्रेणी ''अनु0–13'' तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित श्रेणी तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''अनु0–13 देशी स्पिरिट का थोक विक्रय अनु0–14क का अनुज्ञप्तिधारी जो उसके नाम से जिले में कम–से–कम नौ (9) अनु0–14क बाजार रखता हो/रखती हो, तो वह जिले में एक अनु0–13 अनुज्ञप्ति रखने का हकदार होगा।''।	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर;''।

3. उक्त नियमों में, नियम 24 में,–

(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i) प्ररूप अनु0–। में अनुज्ञप्ति के लिए ₹ 50,00,000।'';

(ii) खण्ड (i–ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ख ख) प्ररूप अनु0–4/अनु0–5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:–

(क) अनु0–4/अनु–5 अनुज्ञप्ति 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को दी जाएगी: ₹ 35,00,000

परन्तु अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि

औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टैक्नोलोजी पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है। अनु0–4/अनु0–5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 (मध्यरात्रि) बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। बारों का समय सात लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घन्टे तक बढ़ाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय जिसमें अनु04/अनु0–5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा शामिल है, 15 प्रतिशत की दर से वैट + वैट पर 5 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क आकर्षित करेगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹ 30,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात–दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएंगी। अनु0–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओ तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है :

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹ 15,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु0–3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0–3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खादय वस्तुओं तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैः

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अपनी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एक बार फीस (वन टाईम फीस) के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित (पहचानित) तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, घटनाओं तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0–4/अनु0–5 तथा अनु0–12 ग अनुज्ञप्तिधारियों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की अनुमति से केवल राज्य के बाहर से सीमाशुल्क–बन्धपत्र भाण्डागारण से सीधे रूप से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो एक सप्ताह में ऐसे अनुरोध का निपटान सुनिश्चित करेगा। बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में अनु0–1 ख च से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) की अपनी आपूर्ति लेने के लिए भी अनुमत हैं। इसके अतिरिक्त, अनु0–1 ख च से भिन्न किसी अन्य स्रोत से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने वाले बार अनुज्ञप्तिधारी स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन तथा ब्राण्डी के मामले में ₹ 60.00 प्रति प्रूफ लीटर की दर से परमिट फीस का भुगतान करेगा। परमिट फीस के अतिरिक्त, निर्धारण फीस भारत में बनी विदेशी मदिरा (बीआईओ) पर उद्गृहीत की जाएगी। जब राज्य के बाहर से सीधे रूप से आयातित की गई है। निर्धारण फीस बीयर, वाईन, लिक्युअर तथा साईडर पर ₹ 300.00 प्रति बल्क लीटर की दर से बार अनुज्ञप्तिधारियों के हाथों से उद्गृहीत की जाएगी।'';

(iii) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(v) (i) देशी मदिरा (अनु0–13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिले में ₹ 10.00 लाख रूपये प्रति बाजार होगी। अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹ 2.00 लाख प्रति अनु0–13 की वापसीयोग्य प्रतिपूर्ति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।

(ii) अनु0–13 अनुज्ञप्तिधारी अपने खुदरा ठेके/समूह ठेकों के कमाण्ड क्षेत्रो के भीतर अपना ठेका स्थापित करेगा। यदि कोई भी उपयुक्त भण्डारण बिन्दु कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो इस शर्त में छूट नियन्त्रक (आबकारी) की पूर्व अनुज्ञा से दी जा सकती है।'';

(iv) खण्ड (i–ड.ड.ड.ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–ड.ड.ड.ड.) प्ररूप अनु0–1 ख च में अनुज्ञप्ति के लिएः–

''(क) एक वर्ष में 5,000 पेटियों से अनधिक के विक्रय के लिए ₹ 10,00,000/–;

''(ख) एक वर्ष में 5,000 पेटियों के प्रत्येक पश्चात्वर्ती स्लैब से अधिक के विक्रय के लिए ₹ 8,00,000/–

निर्धारण फीस

(क) स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन, ब्राण्डी इत्यादि	₹ 500/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख) बीयर	₹ 150/– प्रति बल्क लीटर
(ग) वाईन, लिक्अर, साईडर	₹ 200/– प्रति बल्क लीटर

ब्राण्ड लेबल फीस

(क) स्कोच/विस्की	₹ 40,000 प्रति ब्राण्ड

(ख) बीयर	₹ 40,000 प्रति ब्राण्ड
(ग) रम/वोदका/वाईन	₹ 20,000 प्रति ब्राण्ड
(घ) जिन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन/लिक्अर	₹ 10,000 प्रति ब्राण्ड ;

(v) खण्ड (i–छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(i–छ) प्ररूप अनु0–1–ग में अनुज्ञप्ति के लिए		प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
(i)	विस्की/स्कोच	₹ 75,000 प्रति ब्राण्ड
(ii)	बीयर	₹ 60,000 प्रति ब्राण्ड
(iii)	रम	₹ 40,000 प्रति ब्राण्ड
(iv)	जिन/वोदका	₹ 25,000 प्रति ब्राण्ड
(v)	वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन	₹ 15,000 प्रति ब्राण्ड
(vi)	सीएसडी की आपूर्ति के लिए वोदका/ब्राण्डी/ साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन	₹ 1,000 प्रति ब्राण्ड
(vii)	देशी मदिरा	₹ 75,000 प्रति ब्राण्ड
(viii)	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 60,000 प्रति ब्राण्ड'';

(vi) खण्ड (ii–ख) में, ''विशेषाधिकार फीस'' शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''विशेषाधिकार फीस

भारत मे बनी विदेशी स्पिरिट	₹ 12.00 प्रति प्रूफ लीटर
बीयर	₹ 9.00 प्रति बल्क लीटर'';

(vii) खण्ड (ii–ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ii–ग) आई एम एफ एस पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगीः–

''(ii–ग) (क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹8.00/– प्रति प्रूफ लीटर
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लाटं बाटलिगं के लिए	₹12.00/– प्रति प्रूफ लीटर
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिगं के लिए	₹14.00/– प्रति प्रूफ लीटर

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्गृणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रैन्चाईज) फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।'';

(viii) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु प्ररूप अनु0–12 क में अनुज्ञप्ति ₹500 प्रतिदिन समारोह के भुगतान पर एक दिन के लिए कब्जा सीमा से बाहर प्राईवेट स्थान पर व्यक्तिगत के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा दी जा सकती है। वाणिज्यिक स्थानों जैसे कि समारोह आयोजित करने, एकत्र होने के लिए बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं को ₹ 25000 प्रतिवर्ष की रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान पर जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। ऐसे मामलों में फीस ढांचा निम्न अनुसार होगाः–

(क) आबकारी विभाग से रजिस्टर्ड वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए	₹5000 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ख) वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए जो आबकारी विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है।	₹10,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

वाणिज्यिक स्थानों पर समारोह करने वालों को इसके अतिरिक्त हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23) के अधीन रजिस्टर्ड कराना होगा। वाणिज्यिक स्थान जो विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है, को प्रतिमास पॉच अनुज्ञप्तियों से अधिक जारी नहीं की जाएगी। सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु0–12 क अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवदेन में प्रबन्धक के ब्योरे अर्थात् नाम तथा शैली, टिन इत्यादि तथा मेहमानों की लगभग संख्या वर्णित होगी।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 36–क में,–

(i) उप–नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(14) सफल आबंटितियों की सूची सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची विभाग की कार्यालय वेबसाईट अर्थात् डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.हरियाणाटैक्स.गोव.इन पर भी प्रदर्शित की जाएगी।'';

(ii) उप–नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन निगम तथा नगरपालिका निकायों की भूमि में सम्भाव्य उच्च राजस्व वाले मदिरा ठेकों की स्थापना के लिए कुछ स्थान किराए पर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसे स्थान मुहैया कराएगा। अभिकरणों को किराया विभाग द्वारा दिया जाएगा। अनु0–2 ठेके पर्यटक कम्पलैक्सों में खोले जाएंगे। ऐसे ठेकों के लिए स्थान हरियाणाा पर्यटन निगम द्वारा प्रीफिक्स किराए तथा अन्य निबन्धनों तथा शर्तों पर मुहैया कराया जाएगा। हरियाणा पर्यटन निगम ठेके के लिए पूर्वनिर्मित ढॉचे के निर्माण के लिए स्थान देगा या अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा मुहैया स्थान पर पूर्वनिर्मित ढांचा निर्मित करेगा। कोई भी अनुमत कक्ष इन अनु0–2 ठेकों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त(आबकारी) शहरी ठेके के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा तथा किसी समूह ठेके के पुनः स्थान निर्धारण के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा उक्त समूह के अधिकार क्षेत्र के भीतर अनुज्ञात करेगा।''; तथा

(iii) उप–नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

(24) शहरी क्षेत्रों की पाश मार्किट या शापिंग मॉलों में भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–2) के कुछ खुदरा ठेकों को पहचाना गया है तथा आधुनिक दुकानों के रूप में आबंटित किए जाने हैं। आधुनिक दुकानों को क्षेत्र के ग्राहक–गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। आधुनिक दुकानों में भारतीय विदेशी मदिरा (बीआईओ) का पृथक् वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें बिना किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर जो मूल कोटे अर्थात् 50 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे के स्लैब को लागू है, अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगाः

परन्तु मशीन जनरेटिड बीजक (पीओएस) व्यवस्था ₹3 करोड़ के बराबर या से अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्रों के सभी अनु0–2 अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विस्तारित की जाएगी। परन्तु यह और कि यदि ₹ 2 करोड़ के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु0–2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद आधुनिक दुकान में अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी (समिति) द्वारा परीक्षित किया जा सकता है तथा अनुमोदन के लिए विचारा जा सकता है।

(25) खुदरा अनुज्ञप्त मदिरा बाजार/समूह बाजार को प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए अनुज्ञप्त बाजार/समूह बाजार की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के ₹ 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई–बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2016 तक जमा कराई जाएगी। उसके बोली धन का 83 प्रतिशत उसके बोली धन के 8.3 प्रतिशत की दस बराबर मासिक किश्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तारीख तक तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 17 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) उसके बोली धन के 4 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2017 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में

असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

(27) ठेकों/समूह ठेकों की दशा में जो वित्तीय वर्ष की चालूता के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन के तिथि के दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेका/समूहठेका आबंटन/पुनः आबंटन की तिथि के आगामी दिन से प्रचालन में आएगा। मास जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तो में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

दिसम्बर, 2016 के बाद हुए आबंटन पुनः आबंटन के मामले में, उसके बोली धन का 83 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

यदि आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व तो भुगतान की तिथि 20 होगी। यदि आबंटन 20 को या बाद में तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा। कोई भी ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप–नियम 16 में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(छ) (क) उप–ठेका खोलने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को नीचे वर्णित पैरा (ड.) के अनुसार के सिवाय प्रति उप–ठेके ₹ 1,25,000/–की नियत वार्षिक फीस के भुगतान पर प्ररूप अनु0–14क/एसवी में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उप–ठेका ग्रामीण देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा ठेका दोनों के ठेके/समूह ठेके के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किन्हीं गाँवों में उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा;

(ख) उप–ठेके 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप–ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की सिफारिश पर नियन्त्रक (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

(घ) उप–ठेका उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किया जाएगा जहां मुख्य ठेका अवस्थित हैं, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है; तथा

(ड.) 2000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में स्थित उप–ठेके के लिए फीस ₹ 50,000/– प्रति उप–ठेका होगी।''।

श्यामल मिश्रा,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. 9/X-1/P.A.1/1914/S.59/2016.— In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 14/X-1/P.A.1/1914/S. 59/2015, dated the 31st March, 2015, I, Shyamal Misra, Excise Commissioner, Haryana exercising the powers of Financial Commissioner hereby makes the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2016.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules) in rule 2, in the table,

under heading "Country Spirit-II", for class "L-13" and entries thereagainst, the following class and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"L-13 Wholesale vend of country spirit. The licensee of L-14A who has minimum of nine (9) L-14A outlets in the District in his name shall be entitled to have one L-13 license in the district.	Fixed fee	Collector	Collector;".

3. In the said rules, in rule 24,-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) for a license in form L-1 ₹ 50,00,000.".

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

(a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above: ₹ 35,00,000

Provided that L-4/L-5 licensees shall also be granted in emerging residential townships and such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/ Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula:

Provided further that such licensees shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. L-4/L-5 licensee bars can remain open upto 12.00 hours (Midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of Rs. 7 Lac. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 15 % + surcharge @ Rs. 5% on VAT.

(b) Hotels having grading of 4 Star ₹30,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

(c) Hotels having grading of 3 Star ₹15,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in upto three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one – time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 and L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) directly from Custom Bonded Warehouses, only from outside the State, with the permission Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned who shall ensure disposal of such a request within a week. The bar licensees are also allowed to take their supplies of Imported Foreign Liquor (BIO) from L-1BF in the State. Further, the bar licensees procuring Imported Foreign Liquor (BIO) from any other source other than L-1BF shall pay a permit fee at the rate of ₹. 60.00 per Proof Litre in case of Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin and Brandy. In addition to the permit fee, an assessment fee will be levied on India Made Foreign Liquor (BIO) when imported directly from outside the State. The assessment fee shall be levied at the hands of bar licensees at the rate of ₹ 300.00 per Bulk Litre on beer, wine, Liquir and cider.".

(iii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :-

"(v) (i) The annual license fee for the wholesale outlets of country liquor (L-13) shall be ₹ 10.00 lac per outlet in the district. The licensee shall be required to deposit a refundable security amount of ₹ 2.00 lac per L-13 outlet in the district.

(ii) The L-13 licensee shall establish his vend within the command area of his retail vend/group of vends. In case no suitable storage point is available in the command area, this condition may be relaxed with the prior permission of the Collector (Excise).".

(iv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

" (i-eeee) For a license in form L-1BF. –

"(a) Rs. 10,00,000/- for sale not exceeding 5,000 cases in a year;

(b) Rs. 8,00,000/- for sale exceeding every subsequent slab of 5,000 cases in a year.";

ASSESSMENT FEE

(a)	Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy etc.	₹ 500 per Proof Litre
(b)	Beer	₹ 150 per Bulk litre
(c)	Wine, Liqueur, Cider	₹ 200 per Bulk litre

Brand Level Fee

(a)	Scotch/Whisky,	₹ 40,000 per brand
(b)	Beer	₹ 40,000 per brand
(c)	Rum/Vodka/Wine	₹ 20,000 per brand
(d)	Gin/Brandy Cider/Champagne/Liqueur	₹ 10,000 per brand

(v) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely : -

"(i-g) For a license in form L-1-C		Annual fee at the rates given below against each: -
(I)	Whisky/ Scotch/	₹75,000 per brand
(II)	Beer	₹60,000 per brand
(III)	Rum	₹40,000 per brand
(IV)	Gin/Vodka	₹25,000 per brand
(V)	Wine/Brandy/Cider/Champagne	₹15,000 per brand
(VI)	Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD	₹1,000 per brand
(VII)	Country Liquor	₹75,000 per brand
(VIII)	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹60,000 per brand.".

(vi) In clause (ii-b), for heading "Franchise Fee" and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely : -

"**Franchise Fee**

Indian Made Foreign Spirit	₹ 12.00 per proof litre
Beer	₹ 9.00 per bulk litre";

(vii) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely : -

"(ii-c) bottling fee on Indian Made Foreign Spirit shall be levied as under: -

(a)	for D-2 licenses bottling their own brands	₹ 8.00/- per Proof Litre
(b)	for bottling plants bottling their own brands	₹ 12.00/- per Proof Litre
(c)	for bottling of brands not covered in (a) and (b) above	₹ 14.00/- per Proof Litre

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

(viii) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that a license in form L-12A may be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) to an individual at private place beyond possession limit for a day on payment of ₹ 500 per day function.

The commercial places like banquet halls, farm houses, community centres, dharamshalas holding functions, get-togethers shall have to be registered with the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District on payment of a registration fee Rs. 25,000/- per annum. The fee structure in such cases shall be as under:-

(a)	for persons serving liquor at commercial places registered with Excise department.	₹5,000 per day per function
(b)	for persons serving liquor at commercial places not registered with Excise department.	₹10,000 per day per function

The commercial places holding functions shall have to be registered under the Haryana Tax Luxury Act, 2007 (23 of 2007) as well. The commercial venues not registered with the department shall not be issued more than 5 licenses per month. The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall mention the details of caterer i.e. name and style, TIN etc. and approximate number of guests.".

4. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for sub- rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(14) The list of successful allottees shall be displayed at a conspicuous place in the office of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the respective district. The list shall also be displayed on official website of the Department i.e. www.haryanatax.gov.in.".

(ii) for sub- rule (22), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(22) The Excise and Taxation Department shall hire some locations for setting up liquor vends having high revenue potential in Haryana Urban Development Authority Area and the land of Haryana Tourism Corporation and Municipal Bodies. The rent shall be paid by the department to the agencies. The L-2 vends shall be opened in tourist complexes. The space for such vends shall be provided by Haryana Tourism Corporation on prefixed rent and other terms and conditions. The Haryana Tourism Corporation shall provide space for erecting a prefabricated structure for the vend or the licensee shall erect a prefabricated structure on the space provided by the Haryana Tourism Corporation. No Anumat Kaksh shall be allowed with these L-2 vends. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall be competent to determine the command area for the urban vends and for relocation of any vend of a group shall be permitted within the command area of the said group by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .".

(iii) for sub- rules (24) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(24) Some retail vends of Indian Made Foreign Liquor (L-2) in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified and to be allotted as Modern Shops. The Modern Shops shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The modern shops shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The modern shops shall be entitled to lift an additional quota upto 10% of his basic quota without any additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as is applicable to basic quota i.e. from the slab of 50% additional quota:

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be extended to all the L-2 licensees in urban areas having license fee equal to or above ₹ 3 crore. It is provided further that if any L-2 Licensee in urban areas having license fee equal to or above ₹ 2 crore, wants to convert his vend into a Modern Shop after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.

(25) Every successful allottee of retail licensed liquor outlets/ group of outlets shall be required to deposit a security amount equal to ₹ 21% of the annual license fee of the licensed outlet/group of outlets, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, whichever is earlier; and the remaining security equal to 11% of the license fee shall be deposited by 7th of April, 2016. The 83% of his bid money shall be payable by him in ten equal monthly installments equal to 8.3% of his bid money; each payable by 20th of each month starting from the month of commencement of his operation of vend/group of vends, and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 83% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 17% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 83% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of two months in two equal installments; each equal to 8.5% of his bid money.

(26) The balance security equal to 4% of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 15th April, 2017. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum.

(27) In case of vends/groups of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 11% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The vend/group of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be payable upto January in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2016, the 83% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 20th. If allotment takes place before 20th or the last day of the month if allotment takes place on or after 20th. No interest shall be payable on the security amount.".

5. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A/SV on payment of fixed annual fee of ₹ 1,25,000/- per sub vend except as per para (e) mentioned below. The sub vend shall be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), in any of the villages within the command area of the vend/group of vends for both rural country liquor and Indian made foreign liquor vend .".

(b) Sub-vends will be allowed for each Gram Panchayat with a population more than 1000 (as per 2011 census).

(c) Sub-vends for a Gram Panchayat having population less than 1000 (as per 2011 census), shall be allowed with the consent of the Gram Panchayat, by the Collector (Excise), on the recommendation of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).

(d) A sub-vend shall be allowed in a Gram Panchayat where the main vend is located, if the population of such Gram Panchayat is more than 5000 (as per 2011 census).

(e) The fee for a sub vend located in a Gram Panchayat having population less than 2000 (as per 2011 census) shall be ₹ 50,000 per sub-vend.".

SHYAMAL MISHRA,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 10/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 31 तथा 32/2016.— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 31 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये आदेश पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2016, कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू होंगे।

2. पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, आदेश 1–क में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''सारणी

क्रम संख्या	मदिरा या स्पिरिट की किस्म	शुल्क की दर
1	2	3
1	देसी मदिरा	₹ 1.50 प्रति प्रूफ लीटर
2	बीयर	₹ 0.75 प्रति बोतल 650 मिली लीटर
3	पीने के लिए तैयार पेय	₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर
4	ड्राट बीयर	₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर
5	देसी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
6	अन्यथा पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
7	परिशुद्ध अल्कोहल	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
8	क्रम संख्या 9 के सिवाय डेनचर्ड स्पिरिट	₹ 0.75 प्रति बल्क लीटर
9	ऑटोमोबाइल इंधन के लिए इथानॉल/ डेनचर्ड स्पिरिट	₹ 1.50 प्रति बल्क लीटर
10	भारत में बनी विदेशी स्पिरिट	₹ 1.50 प्रति प्रूफ लीटर।''।

3. उक्त आदेश में, आदेश 1–ड. में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''1.	देशी मदिरा	₹ 1.00 प्रति प्रूफ लीटर
2.	बीयर	₹ 10.00 प्रति बल्क लीटर
3.	पीने के लिए तैयार पेय	₹ 4.00 प्रति बल्क लीटर
4.	ड्राट बीयर	₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर
5.	देशी शराब तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹ 6.00 प्रति बल्क लीटर
6.	औद्योगिक प्रयोग के लिए रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	₹ 3.00 प्रति बल्क लीटर
7.	परिशुद्ध अल्कोहल	₹ 6.00 प्रति बल्क लीटर
8.	क्रम संख्या 9 के सिवाय डेनचर्ड स्पिरिट	₹ 3.00 प्रति बल्क लीटर
9.	ऑटोमोबाईल ईंधन के लिए डेनचर्ड एथनाल/ डेनचर्ड स्पिरिट	₹ 1.00 प्रति बल्क लीटर
10.	भारत में बनी विदेशी स्पिरिट, रम	₹ 16.00 प्रति प्रूफ लीटर
11.	वाईन, साईडर	₹ 4.00 प्रति बल्क लीटर।''।

4. उक्त आदेश में, आदेश 5 में, विद्यमान खण्डों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(i)	बीयर जिसमें 5.5 प्रतिशत तक अल्कोहल की मात्रा हो	₹ 25.00 प्रति बल्क लीटर
(ii)	बीयर जिसमें 5.5 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो	₹ 30.00 प्रति बल्क लीटर
(iii)	डिब्बाबन्द बीयरः	
	(क) नरम	₹ 35.00 प्रति बल्क लीटर
	(ख) शक्तिशाली	₹ 40.00 प्रति बल्क लीटर
(iv)	देशी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर	₹ 18.00 प्रति प्रूफ लीटर
(v)	भारत में बनी विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क की दर	₹ 45.00 प्रति प्रूफ लीटर।''।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 1st April, 2016

No. 10/X-1/P.A.1/1914/S.31 and 32/2016.— In exercise of the powers conferred by sections 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932, in their application to the State of Haryana, namely: -

1. (1) These orders may be called the Punjab Excise Fiscal (Haryana Amendment) Orders, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2016.

2. In the Punjab Excise Fiscal Orders, 1932 (hereinafter called the said orders), in order 1-A, for the existing table the following table shall be substituted, namely:-

"Table

Sr. No.	Kind of liquor or spirit	Rate of duty
1	2	3
1.	Country Liquor	₹ 1.50 per proof litre
2.	Beer	₹ 0.75 per bottle of 650 ml
3.	Ready to Drink Beverages	₹ 1.00 per bulk litre
4.	Draught Beer	₹ 1.00 per bulk litre
5.	Potable Rectified Spirit for Country Liquor	₹ 1.50 per bulk litre
6.	Potable Rectified Spirit otherwise	₹ 1.50 per bulk litre
7.	Absolute Alcohol	₹ 1.50 per bulk litre
8.	Denatured Spirit except as at Serial Number 9	₹ 0.75 per bulk litre
9.	Ethanol/Denatured spirit for Automobile fuel	₹ 1.50 per bulk litre
10.	Indian Made Foreign Spirit	₹ 1.50 per proof litre.".

3. In the said order, in order 1-E, for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

1.	Country Liquor	₹ 1.00 per proof litre
2.	Beer	₹ 10.00 per bulk litre
3.	Ready to Drink Beverages	₹ 4.00 per bulk litre
4.	Draught Beer	₹ 1.00 per bulk litre
5.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	₹ 6.00 per bulk litre
6.	Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Industrial use	₹ 3.00 per bulk litre
7.	Absolute Alcohol	₹ 6.00 per bulk litre
8.	Denatured Spirit except as at Serial Number 9	₹ 3.00 per bulk litre
9.	Denatured Ethanol/Denatured spirit for Automobile fuel	₹ 1.00 per bulk litre
10.	Indian Made Foreign Spirit, Rum	₹ 16.00 per proof litre
11.	Wine, Cider	₹ 4.00 per bulk litre.".

4. In the said order, for order 5, for the existing clauses the following clauses shall be substituted, namely:-

" (i)	Beer containing alcoholic contents upto 5.5%	₹ 25.00 per bulk litre
(ii)	Beer containing alcoholic contents more than 5.5%	₹ 30.00 per bulk litre

(iii)	Canned Beer:	
	a. Mild	₹ 35.00 per bulk litre
	b. Strong	₹ 40.00 per bulk litre
(iv)	The rate of additional excise duty on country liquor	₹ 18.00 per proof litre
(v)	The rate of additional excise duty on Indian Made foreign Liquor.".	₹ 45.00 per proof litre.".

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 11/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 18, 34 तथा 59/2016.— पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 18, 34 तथा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 18, 34 तथा 59/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 के प्रति निर्देश से, मैं, श्यामल मिश्रा, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, अप्रैल, 2016 के प्रथम दिन से पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते है।

2. पंजाब मदिरा अनुज्ञापत्र तथा पारपत्र नियम, 1932 (जिन्हें इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित दरों पर मदिरा के क्रय के लिए परमिट फीस का भुगतान करेगा:–

क्रम संख्या	मदिरा की किस्म	दरें
1.	देशी मदिरा	शून्य
2.	भारत में बनी विदेशी मदिरा	
	2.1 ₹1200 प्रति केस तक ईडीपी सहित ब्रांड	₹ 3/–प्रति प्रूफ लीटर
	2.2 ₹1201 से ₹3000 प्रति केस तक ईडीपी सहित ब्रांड	₹ 3/–प्रति प्रूफ लीटर
	2.3 ₹3001 से ₹6000 प्रति केस तक ईडीपी सहित ब्रांड	₹ 3/–प्रति प्रूफ लीटर
	2.4 ₹6000 प्रति केस से अधिक की ईडीपी सहित ब्रांड	₹ 3/–प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर	
	(i) 5.5 प्रतिशत तक मादक मात्रा वाली बीयर	₹ 2/–प्रति प्रूफ लीटर
	(ii) 5.5 प्रतिशत से अधिक मादक मात्रा वाली बीयर	₹ 2/–प्रति प्रूफ लीटर
	(iii) डिब्बाबन्द बीयर:	
	(क) नरम	₹ 2/–प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) शक्तिशाली	₹ 2/–प्रति प्रूफ लीटर
4.	आटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग के लिए एथानल	₹ 1/–प्रति बल्क लीटर
5.	ड्राट बीयर	₹ 2/–प्रति बल्क लीटर
6.	साइडर	शून्य
7.	मीठी वाईन	
	(क) 25 डिग्री तक स्पिरिट सहित	शून्य
	(ख) 25 डिग्री से अधिक स्पिरिट सहित	शून्य
8.	पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 2/–प्रति बल्क लीटर
9.	देशी शराब तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए पोटेबल रैक्टीफाईड स्पिरिट तथा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	शून्य

10.	आटोमोबाईल ईंधन में प्रयोग हेतु के सिवाय विकृत स्पिरिट/एथानल	₹ 3/–प्रति बल्क लीटर
11.	औद्योगिक प्रयोग के लिए आरएस तथा ईएनए	₹ 3/–प्रति बल्क लीटर

3. उक्त नियमों में, नियम 22–क में, उप नियम (1) में, ''आजीवन के लिए 2000/–रूपये'' शब्दों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, ''दस वर्ष के लिए 1500/–रुपये'' शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

श्यामल मिश्रा,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. 11/X-1/P.A.1/1914/Ss.18, 34 and 59/2016.— In exercise of the powers conferred by sections 18, 34 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 12/X-1/P.A.1/1914/Ss. 18, 34 and 59/2015, dated the 31st March, 2015, I, Shyamal Misra, Excise Commissioner, Haryana, hereby make the following rules further to amend the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, with effect from the 1st day of April, 2016, namely :-

1. These rules may be called the Punjab Liquor Permit and Pass (Haryana Amendment) Rules, 2016.

2. In the Punjab Liquor Permit and Pass Rules, 1932 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in clause (a), for the existing second proviso the following proviso shall be substituted, namely : -

"Provided further that the licensee shall pay permit fee for the purchase of liquor on the following rates : -

Serial Number	Type of Liquor	Rates
1.	Country Liquor	Nil
2.	Indian Made Foreign Spirit	
	1.1 Brands with Ex-Distillery Issue Price upto Rs. 1200 per case	₹ 3 Per Proof Litre
	1.2 Brands with Ex-Distillery Issue Price from Rs. 1201 upto 3000 per case	₹ 3 Per Proof Litre
	1.3 Brands with Ex-Distillery Issue Price from Rs. 3001 upto 6000 per case	₹ 3 Per Proof Litre
	2.4 Brands with Ex-Distillery Issue Price of more than Rs. 6000 per case	₹ 3 Per Proof Litre
3.	BEER	
	(i) Beer containing alcoholic content upto 5.5%	₹ 2 Per Bulk Litre
	(ii) Beer containing alcoholic content more than 5.5%	₹ 2 Per Bulk Litre
	(iii) Caned Beer :	
	(a) Mild	₹ 2 Per Bulk Litre
	(b) Strong	₹ 2 Per Bulk Litre
4.	Ethanol for use in automobile Fuel	₹ 1 Per Bulk Litre
5.	Draught Beer	₹ 2 Per Bulk Litre
6.	Cider	Nil
7.	Sweet Wine	
	(a) With spirit upto 25 degree	Nil
	(b) With spirit more than 25 degree	Nil
8.	Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 2 Per Bulk Litre
9.	Potable Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor	Nil

10.	Denatured spirit/Ethanol except for use in automobile fuel	₹ 3 Per Bulk Litre
11.	Rectified Spirit and Extra Neutral Alcohol for industrial use	₹ 3 Per Bulk Litre".

3. In the said rules, in rule 22-A, in sub rule (1), for the word, figures and sign, "Rs. 2000/- for life time", the words, figures and sign, "Rs. 1500/- for ten years" shall be substituted.

SHYAMAL MISRA,
Excise and Taxation Commissioner.
Haryana.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 12/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 58/2016.— चूंकि, राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) संशोधन नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

(2) ये प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू होंगे।

2. हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(1) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, प्ररूप अनु0–52 (अनुमत कक्ष) में अनुज्ञप्ति तथा उसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन ठेके की अनुज्ञप्ति फीस के दो प्रतिशत पर दिया जा सकता है जो अनुमत कक्ष की अनुज्ञप्ति फीस के रूप में न्यूनतम ₹ एक लाख के अध्यधीन नियत किया जायेगा। यदि जहां ठेका समूह का भाग है, तो ठेके की अनुज्ञप्ति फीस जिसके लिए अनुमत कक्ष को, अनुमत कक्ष के लिए अनुज्ञप्ति फीस पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए समूह के प्रत्येक ठेके के लिए आबंटित मूल कोटे के अनुपात में समूह के सभी ठेकों के बीच समूह अनुज्ञप्ति फीस विभक्त करते हुए संगणित किया जाएगा। अनुमत कक्ष को बिना सीमा के खुले स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। स्थान परिरूद्ध तथा बन्द के रूप में होगा तथा आम जनता द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे आम रास्ते या क्रासिंग में नहीं होगा। स्थान साधारणतः राहगीर दृश्य नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। सम्पूर्ण उद्देश्य राहगीर के सम्पूर्ण विचार में लोगों में शराब पीने से रोकना है। अनुमत कक्ष केवल ठेके तथा उसी परिसर में निकटवर्ती स्थान में चलाया जाएगा। अनुमत कक्ष का क्षेत्र अनुमत कक्ष के अनुमोदन के समय पर उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। शराब अनुमत कक्ष में किसी भी रीति में बेची या परोसी नही जाएगी। जनता में हुल्लड़बाज (उपद्रवी) तथा पियक्कड़ व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से, प्रत्येक खुदरा ठेके में एक अनुमत कक्ष सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/समिति की बाहरी सीमा तथा अन्य राज्यों की सीमा (बार्डर) से 5 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों में मदिरा (अनु–14क/अनु–2) के प्रत्येक खुदरा बाजार के लिए आबकारी नीति तथा सम्बन्धित आबकारी नियमों/मादक अनुज्ञप्ति तथा विक्रय आदेश, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कठोर रूप से उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखना अपेक्षित है।''।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. 12/X-1/P.A.1/1914/S.58/2016.— Where the State Government considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2016.

2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to other provisions of these rules, a license in form L-52 (Anumat Kaksh) and subject to the conditions contained therein may be granted on 2% of license fee of the vend subject to a minimum of one lac rupees as license fee of the Anumat Kaksh. In case where the vend is part of the group, the license fee of the vend for which Anumat Kaksh shall be computed by dividing the group license fee among all the vends of the group in the ratio of basic quota allotted to each vend of the group for the purpose of arriving at the license fee for Anumat Kaksh. The Anumat Kaksh shall not be operated in an open space without boundary. The space shall to be confined and enclosed and shall not be a thorough fare or a crossing being used by general public. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well defined entry. The overall objective is to prevent drinking in public in full view of the passersby. Anumat Kaksh shall only be operated from adjoining place to the vend and in the same premises. The area of Anumat Kaksh shall be approved by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Anumat Kaksh and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Anumat Kaksh. In order to prevent rowdy and drunken behavior in public, one Anumat Kaksh with each retail vend, shall be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) strictly as per the provisions of the Excise Policy and relevant Excise Rules/Intoxicants License and Sales Orders 1956, for each retail outlet of liquor (L-14A/ L-2) in urban areas and sub-urban areas falling within 5 Kilometers from the outer limit of respective Municipal Corporation/Council/Committees and borders with other States. The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment.".

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 2/22/2015–आर0–II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम–1973 (1973 का 24) की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या 2/22/2015–आर–II दिनांक 29 जनवरी, 2016 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा नगरपालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबन्धन नियम 2007 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित बनाते है अर्थातः–

1. यह नियम हरियाणा नगर पालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबन्धन (संशोधन) नियम 2016 कहे जा सकते हैं।

2. नगर पालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबन्धन नियम 2007 के नियम 7 में उप–नियम 2 में ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''उपायुक्त'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. 2/22/2015-RII.— In exercise of the powers conferred by clause (n) of Sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference Haryana Government Urban Local Bodies Department notification No.2/22/2015-RII dated the 29th January, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties (Amendment) Rules 2016.
2. In the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules-2007, in sub-rule (2) for the words "State Government", the words "Deputy Commissioner" shall be substituted.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या पी0एफ0 27ए0/6519.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 8), की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन वहन करने योग्य आवासन प्लॉटिड पॉलिसी, 2016 अर्थात दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, को उक्त पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट सभी निबन्धनों, शर्तों तथा पॉलिसी पैरामीटर की सुस्पष्ट स्वीकृति देने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गए वचन को प्रस्तुत करने के अधीन, उक्त पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार निदेशक द्वारा अवसंचरना विकास प्रभारों, परिवर्तन प्रभारों तथा अनुज्ञप्ति फीस तथा बाह्य विकास प्रभारों की सीमा तक भुगतान से छूट देते हैं।

पी0 राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. PF-27A/6519.— In exercise of the powers conferred by section 23 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Governor of Haryana hereby exempts all such persons who submit application for grant of licence under the Affordable Plotted Housing Policy, 2016 namely Deen Dayal Jan Awas Yojna under section 3 of the said Act, from payment of infrastructure development charges, conversion charges and limit the recovery of license fee and external development charges by the Director as per the rates specified under the said policy, subject to submission of an undertaking by such person conveying unequivocal acceptance of all terms, conditions and policy parameters specified under the said policy.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretray to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2016

No. PF-27A/6521.— The Governor of Haryana is pleased to notify an 'Affordable Plotted Housing Policy 2016 for Low and Medium Potential Towns: Deen Dayal Jan Awas Yojna', under the provisions of Section 9A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 as well as under Section 11 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and any other corresponding statute governing development of plotted housing colonies on the subject, provided that if there is any contradiction in any other provision relating to the development of such colonies then the provisions of this policy shall prevail.

The policy, of which the details are given in Annexure-A below, has been concurred by the Finance Department vide their UO No. 11/161/2015-5FDIII/2850 dated 02nd February, 2016 and approved by the Council of Ministers in its meeting held on 03rd February, 2016. This policy shall come into effect from the date of its issuance. The Director General, Town and Country Planning, Haryana, is hereby directed to effectively implement this policy to facilitate creation of additional affordable housing stock in the Low and Medium Potential Towns of the State.

ANNEXURE-A

AFFORDABLE PLOTTED HOUSING POLICY 2016: DEEN DAYAL JAN AWAS YOJNA

1. Forward:

(i) This policy shall be known as 'Deen Dayal Jan Awas Yojana'. This policy is intended to encourage the development of high density plotted colonies in Low and Medium Potential towns of the State wherein small plots are made available through a liberal policy framework.

(ii) All such projects shall be required to be necessarily completed within 7 years (5+2 years) from the date of grant of licence.

2. Siting Parameters:

(i) The projects under this policy shall be allowed only in the residential zone of the notified Development Plans of Low and Medium Potential towns of the State. Further, in any residential sector not more than 30% of the net planned area under residential zone, inclusive of the 20% area limit allowed for group housing projects, can be allowed for projects under this policy. However, if a residential sector has an area of less than 50 acres, one such project shall be allowed upto 15 acres.

(ii) The minimum and maximum net planned area for such projects shall be 5 acres and 15 acres respectively irrespective of the Development Plan where such project is proposed. Not more than 10% of the licenced area should fall under sector roads.

(iii) The first licence may be obtained for an area of 5 acres or more and additional licence for minimum 2 acres can be obtained to take the aggregated area of colony upto 15 acres.

(iv) Grant of licence shall be considered under this policy, initially, against 20% group housing area limit in such sector. Once the area under 20% limit stands exhausted on account of either group housing licences or affordable housing policy 2013 projects or under the present policy; grant of any further licence under this policy shall be considered only upto a further limit of 10% of the net planned area under residential zone of such sector.

3. Receipt Of Applications & Their Eligibility:

(i) The applications for licence received under this policy should be made in the format as prescribed in the Rule 3 of the Haryana Development and Regulations of Urban Areas Rules, 1976 and the said Rules shall be applicable mutatis-mutandis for processing of the application under this policy.

(ii) The opening window for receipt of licence applications under this policy shall be 90 days from the notification of this policy. During this period-

(a) In case, the receipt of licence applications in a particular sector for area is less than the total area permitted in that sector under this policy, then all the eligible applications shall be considered for grant of licence subject to the minimum area norm of 5 acres and maximum area norm of 15 acres.

(b) In case the receipt of licence applications in a particular sector for area is more than total area permitted in that sector under this policy, then: -

(i) Every applicant shall be eligible for minimum 5.00 acres and the balance area shall be allowed to every applicant in proportion to the balance permitted area viz-a-viz balance applied area.

(ii) However, if all the applications cannot be accommodated in view of minimum area norms, then the DGTCP may consider all applications by increasing the permitted area upto 40% of net planned area of residential sector. If all the applications cannot be considered even within 40% of net planned area, then draw of lots shall be conducted.

(iii) Applications shall be entertained on an ongoing basis till the availability of area in any specific sector and/or any specific development plan vis-a-vis the area limits prescribed under this policy gets licenced.

(iv) After receipt of application, complete in all respects, from an applicant, the decision regarding either issuance of LOI or return/rejection of licence application shall be conveyed to the applicant within a period of six months from the receipt of application.

(v) Though the policy does not prescribe any cap on the allotment rate of plots, it is envisaged that with a regular and adequate supply of high density residential plotted colonies under this policy, the market forces shall ensure that the rates of plots are affordable in such colonies.

4. Planning And Area Parameters: The planning and area parameters for the projects allowed under this policy are as follows:

a.	Max area of plots to be permitted:	150 sqm.
b.	Min. and Max. density permitted:	240 to 400 persons per acre (PPA).
c.	Max. area allowed under Res. & Comm. Plots:	65% of the licenced area
d.	Area under Commercial Use:	Max. 4% of licenced area.
e.	Max. FAR on Res. plot of upto 150 sqm:	2.00
f.	Min. width of Internal roads in the colony:	9 metre
g.	Minimum Area under organized Open Space:	7.5% of the licenced area.

The entire area prescribed under organized open space shall preferably be provided in a single pocket of regular shape. At least one organized open space pocket, in each colony, shall be of not less than 0.3 acre area.

h. No separate EWS/NPNL category plots shall be provided to eliminate any cross subsidy component and thus to avoid any adverse impact on the affordability of plots made available under this policy.

i. Clubbing of residential plots for approval of integrated zoning plan of two adjoining plots under same ownership shall not be permitted in the colonies approved under the present policy.

j. The colonizer will transfer 10% area of the licenced colony free of cost to the Government for provision of community facilities. This will give flexibility to the Director to workout the requirement of community infrastructure at sector level and accordingly make provisions. Since the area will be received in a compact block, it will help in optimal utilization of the area.

k. Registration of independent floors in plots shall be allowed.

l. The stilt parking shall be allowed.

5. Allotment Process:

(i) Allotment of 50% residential plots covering saleable area (excluding 50% area frozen by the Department) shall be undertaken in the first phase by the licencee/coloniser. However, the colonizer shall also carry out development works simultaneously on this area also. It is clarified that 15% area mortgaged towards IDW shall be part of 50% area frozen by Department upto completion of IDW in the colony.

(ii) The applicant shall have an option to deposit the cost of internal development works with the concerned Municipality as per mutually decided rates.

(iii) As a matter of security against any possible delinquencies in completion of the project, the coloniser shall be required to mortgage residential plots covering saleable area of not less than 15% of the total area under all residential plots in lieu of depositing cost of IDW with concerned municipality, in favour of the Director.

(iv) The applicant shall be allowed to sell the balance 50% of the saleable area after completion of IDW.

6. Applicable Fees & Charges:

(i) Taking into account the fact that a limited number of projects shall be allowed under this policy, the licence fees shall be levied at the following rates:

1. For medium potential towns: Rs. 1 lakh per acre
2. For low potential towns: Rs. 10 thousand per acre

(ii) The scrutiny fees at prescribed rates shall be levied.

(iii) The Conversion Charges and IDC shall stand waived off.

(iv) The bank guarantee to the tune of 25% on account of IDW shall be submitted or the applicant has to mortgage 15% salable area.

(v) EDC shall be payable at the rate of Rs.10 Lacs per acre for Medium Potential Zone, Rs.7.5 Lacs per acre for all the District Headquarters falling within Low Potential Zone and Rs. 5 Lacs per acre for all other towns falling within Low Potential Zone. The bank guarantee to the tune of 25% on account of EDC shall be submitted by the applicant.

7. Special Dispensations:

(i) The Director may impose any other condition, as considered necessary, to ensure provision of adequate infrastructure services to the colony and for effective implementation of this policy.

(ii) The allotment letter and sale-purchase agreement entered into with the allottees shall also include the parameters prescribed under this policy to maintain complete transparency in the matter.

In order to enable effective and expeditious implementation of this policy to facilitate creation of additional affordable plotted housing stock in the Low and Medium Potential Towns of the State, necessary action pertaining to amendment in Act/ Rules, development plans will be undertaken immediately.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretray to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

शुद्धि–पत्र

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या 13/4/96–2H(C).— हरियाणा सरकार, असाधारण राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 2013 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 13/4/96–2HC, दिनांक 11 जनवरी, 2013 में, मूल हिन्दी पाठ में, नियम 1 में, ''हरियाणा चौकीदार विनियम, 2011'', शब्दों, चिह्न, और अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा चौकीदार नियम, 2013'' शब्द चिह्न और अंक पढ़े जाएं।

पी० के० दास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Corrigendum

The Ist April, 2016

No. 13/4/96-2H(C).— In the Haryana Government, Home Department, Notification No. 13/4/96-2HC, dated the 11th January, 2013 published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 11th January, 2013, in its authorised English translation, in the existing short title for "2011" read "2013",

P. K. DAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या रा0नि0आ0/3ई–11/2016/3478.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 161 की उप–धारा (4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो निम्नलिखित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैं:–

जिला का नाम	खण्ड/पंचायत समिति का नाम	नाम सर्व/श्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम	पद का नाम
जीन्द	जीन्द	नीलम	धर्मबीर	अध्यक्ष
		नरेश कुमार	चतर सिंह	उपाध्यक्ष
	जुलाना	अन्जु	राजेश कुमार	अध्यक्ष
		सुखबीर सिंह	प्रेम सिंह	उपाध्यक्ष
	नरवाना	मोनिका	अरूण सिंह	अध्यक्ष
		विराट	रामकुमार	उपाध्यक्ष
कैथल	राजौंद	रानी देवी	दिलबाग सिंह	अध्यक्ष
		सर्वजीत कौर	इन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष
	पुण्डरी	संगीता रानी	सुनील	अध्यक्ष
		जसबीर सिंह	सेवा सिंह	उपाध्यक्ष
	कलायत	परमवीर सिंह	टेक राम	अध्यक्ष
		आनन्द प्रकाश	शिवचरण	उपाध्यक्ष
	सीवन	अनिता रानी मुन्झाल	नरेश कुमार	अध्यक्ष
		प्रवीन कुमार	महेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष
	गुहला	नेत्रपाल	अमृत लाल	अध्यक्ष
		रामपाल	जूना राम	उपाध्यक्ष
करनाल	इन्द्री	पुनम देवी	दिनानाथ	अध्यक्ष
		सुशील कुमार	बलबीर सिंह	उपाध्यक्ष
रेवाड़ी	रेवाड़ी	उमेश लता	अर्जुन सिंह	अध्यक्ष
		भूपेन्द्र	रतनलाल	उपाध्यक्ष
	बावल	विरेन्द्र सिंह	फूल सिंह	अध्यक्ष
		विक्रम सिंह	भूप सिंह	उपाध्यक्ष
	खोल	अर्चना	यशवन्त	अध्यक्ष
		सुनीता	धमेन्द्र	उपाघ्यक्ष
	जाटूसाना	रूबी यादव	राजकुमार	अध्यक्ष
		मुनेश	सोनू	उपाघ्यक्ष
	नाहड	सुमन देवी	सतीश कुमार	अध्यक्ष
		रवि कुमार	श्याम लाल	उपाघ्यक्ष
सोनीपत	खरखौदा	राजबीर	शीशपाल	अध्यक्ष
		रोहताश	रणधीर	उपाघ्यक्ष
	मुंडलाना	शीला	राजेश	अध्यक्ष
		राजा	मोलड़	उपाघ्यक्ष
	राई	संजय चौहान	विरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
		चेतन	ओमप्रकाश	उपाघ्यक्ष
	सोनीपत	समिता रानी	प्रदीप सिंह	अध्यक्ष
		अजय कुमार	प्रताप सिंह	उपाघ्यक्ष
	मुरथल	सीमा	कृष्ण कुमार	अध्यक्ष
		पवन कुमार	ओमप्रकाश	उपाघ्यक्ष
	गोहाना	बबीता देवी	सुरेश कुमार	अध्यक्ष

पंचकूला:
01 अप्रैल, 2016.

राजीव शर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17, PANCHKULA.

Notification

The Ist April, 2016

No. SEC/3E-II/2016/3478.— In pursuance of the provisions of sub-section(4) of section 161 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the State Election Commissioner, Haryana hereby notifies the names of the following persons, who have been elected as Chairman and Vice-Chairman of the following Panchayat Samitis:-

District	Panchayat Samiti	Name Sh./Smt./Kumari	Father's/Husband's Name Sh.	Name of Office
Jind	Jind	Neelam	Dharmbir	Chairman
		Naresh Kumar	Chattar Singh	Vice-Chairman
	Julana	Anju	Rajesh Kumar	Chairman
		Sukhbir Singh	Prem Singh	Vice-Chairman
	Narwana	Monika`	Arun Singh	Chairman
		Virat	Ramkumar	Vice-Chairman
Kaithal	Rajound	Rani Devi	Dilbag Singh	Chairman
		Sarvjeet Kaur	Inder Singh	Vice-Chairman
	Pundri	Sangeeta Rani	Sunil	Chairman
		Jasbir Singh	Sewa Singh	Vice Chairman
	Kalayat	Paramvir Singh	Tekram	Chairman
		Anand Prakash	Shiv Charan	Vice-Chairman
	Siwan	Anita Rani Munjhal	Naresh Kumar	Chairman
		Parveen Kumar	Mahinder Singh	Vice-Chairman
	Guhla	Netarpal	Amrit Lal	Chairman
		Rampal	Juna Ram	Vice-Chairman
Karnal	Indri	Poonam Devi	Dina Nath	Chairman
		Sushil Kumar	Balbir Singh	Vice-Chairman
Rewari	Rewari	Umesh Lata	Arjun Singh	Chairman
		Bhupender	Rattan Lal	Vice-Chairman
	Bawal	Virender Singh	Phool Singh	Chairman
		Vikram Singh	Bhoop Singh	Vice-Chairman
	Khol	Archana	Yashwant	Chairman
		Sunita	Dharmender	Vice- Chairman
	Jatusana	Ruby Yadav	Raj Kumar	Chairman
		Munesh	Sonu	Vice- Chairman
	Nahar	Suman Devi	Satish Kumar	Chairman
		Ravi Kumar	Shyam Lal	Vice-Chairman
Sonipat	Kharkhoda	Rajbir	Shishpal	Chairman
		Rohtash	Randhir	Vice-Chairman
	Mundlana	Sheela	Rajesh	Chairman
		Raja	Molad	Vice-Chairman
	Rai	Sanjay Chauhan	Virender Singh	Chairman
		Chetan	Omparkash	Vice-Chairman
	Sonipat	Samita Rani	Pardeep Singh	Chairman
		Ajay Kumar	Partap Singh	Vice-Chairman
	Murthal	Seema	Krishan Kumar	Chairman
		Pawan Kumar	Om Parkash	Vice-Chairman
	Gohana	Babita Devi	Suresh Kumar	Chairman

Panchkula:
The 1st April, 2016.

RAJEEV SHARMA,
State Election Commissioner, Haryana.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या रा0नि0आ0/3ई–11/2016/3476.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उप–धारा (4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैंः–

जिला परिषद	नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	पिता/पति का नाम श्री	पद का नाम
कैथल	सुखविन्द्र कौर	हरदीप सिंह	प्रधान
	मुनीश	भले राम	उप–प्रधान
करनाल	उषा देवी	संजय कुमार	प्रधान
	बाला देवी	नरेन्द्र कुमार गोरसी	उप–प्रधान
रेवाड़ी	मन्जू बाला	नेरश कुमार	प्रधान
	जगफूल सिंह	अमर सिंह	उप–प्रधान
सोनीपत	मीना रानी	मनीष कुमार	प्रधान
	बिजेन्द्र	बलजीत सिंह	उप–प्रधान

पंचकूलाः
01 अप्रैल, 2016.

राजीव शर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17, PANCHKULA.

Notification

The Ist April, 2016

No. SEC/3E-II/2016/3476.— In pursuance of the provisions of sub-section(4) of section 161 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the State Election Commissioner, Haryana hereby notifies the names of the following persons, who have been elected as President and Vice-President of Zila Parishad:-

Zila Parishad	Name Sh./Smt./Kumari	Father's/Husband's Name Sh.	Name of Office
Kaithal	Sukhwinder Kaur	Hardeep Singh	President
	Munish	Bhalle Ram	Vice -President
Karnal	Usha Devi	Sanjay Kumar	President
	Bala Devi	Narender Kumar Gorsi	Vice- President
Rewari	Manju Bala	Naresh Kumar	President
	Jagphool Singh	Amar Singh	Vice-President
Sonipat	Meena Rani	Manish Kumar	President
	Bijender	Baljeet Singh	Vice-President

Panchkula:
The 1st April, 2016.

RAJEEV SHARMA,
State Election Commissioner, Haryana.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

शुद्धिपत्र

दिनांक 1 अप्रैल, 2016

संख्या एस0ई0सी0/ई–11/2016/3476.— हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कालम 2 में दर्शायी गई अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2016 के निरंतर में निम्न शुद्धिपत्र को अधिसूचित किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिसूचना क्रमांक	जिला/खण्ड का नाम	अधिसूचना में क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड नं0	नाम श्री/श्रीमती/कुमारी		पिता/पति का नाम		वर्ग	
						पढ़ा जाये	के स्थान पर	पढ़ा जाये	के स्थान पर	पढ़ा जाये	के स्थान पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एस0ई0सी0/ई–II/2016/2046	गुड़गांव/गुड़गांव	9	धर्मपुर	6	रोहित	जोगिन्द्र सिंह	मन्जीत	महाबीर सिंह		
2	एस0ई0सी0/ई–II/2016/2113	करनाल/घरौण्डा	1	अलीपुरखालसा	1			माईचन्द	मईचन्द		
3	–सम–	–सम–	4	ऐंचला	2	*कृष्ण कुमार	कृष्ण लाल	प्रेमचन्द	पुर्णचन्द		
4	–सम–	–सम–	8	बरसत	9	राजेश कुमार	राजैश कुमार				
5	–सम–	–सम–	8	बरसत	सरपंच	महेश कुमार	मेहश कुमार				
6	–सम–	–सम–	11	बेगमपुर	4	*सुषमा	*सुसमा				
7	–सम–	–सम–	14	डीगरमाजरा	5	राजेश	रोजश				
8	–सम–	–सम–	15	फैजलीपुरमाजरा	1	गुलाब सिंह	प्रवीन कुमार	जयपाल	जगदीश चन्द		
9	–सम–	–सम–	15	फैजलीपुरमाजरा	5	कान्ता	कन्ता				
10	–सम–	–सम–	16	फरीदपुर	सरपंच	नरेश कुमार	नेरश कुमार				
11	–सम–	–सम–	17	गगसीना	1	शीला देवी	ीला देवी				
12	–सम–	–सम–	18	गढ़ीभरल	सरपंच	शोकिन कुमार	सोकिन कुमार				
13	–सम–	–सम–	19	गढ़ीखजुर	16	निर्मला कौर	नीरमला कौर				
14	–सम–	–सम–	20	गढ़ीमुल्तान	सरपंच	सुदेश कुमारी	सुदेश कुमार				
15	–सम–	–सम–	24	जमालपुर	4	*रामेश्वर	*रमेश्वर				
16	–सम–	–सम–	25	झिवरहेड़ी	5	जितेन्द्र सिंह	जितैन्द्र सिंह				
17	–सम–	–सम–	27	कैरवाली	4	बाल किशन	बल किशन				
18	–सम–	–सम–	30	खेडीमुनक	3	*शोभा	*सोभा				
19	–सम–	–सम–	37	मुबारकाबाद	2	*रिन्कु	बलबिन्द्र सिंह	रोशन लाल	सुरता राम		
20	–सम–	–सम–	37	मुबारकाबाद	3	*बबीता	*रेखा रानी	सलिन्द्र	राजबीर सिंह		
21	–सम–	–सम–	39	मुण्डीगढ़ी	सरपंच	असजद	असजाद				
22	–सम–	–सम–	39	मुण्डीगढ़ी	3			शीशपाल	शीशपाल		
23	–सम–	–सम–	39	मुण्डीगढ़ी	9			इस्लाम	ईसलाम		
24	–सम–	–सम–	40	पबानाहसनपुर	सरपंच	बलवान	बलवन्त				
25	–सम–	–सम–	40	पबानाहसनपुर	3			पीताम्बर	प्रीतम सिंह		
26	–सम–	–सम–	45	रायपुरजाटान	5	आनन्द	अनन्द				
27	–सम–	–सम–	50	शेखपुराखालसा	7			आनन्द	अनन्द		
28	–सम–	–सम–	52	उपली	1			शीशन सिंह	सिशन सिंह		
29	एस0ई0सी0/ई–II/2016/2117	करनाल/करनाल	62	सोहाना	3	दीपक	विक्रम कुमार	रामफल	बलवान सिंह		
30	एस0ई0सी0/ई–II/2016/2152	करनाल/नीलोखेड़ी	2	नरायणा	2	दलबीर सिंह	जोहन लाल				
31	–सम–	–सम–	5	–सम–	5	साहिब सिंह	कुलदीप सिंह				
32	एस0ई0सी0/ई–II/2016/2089	जीन्द/नरवाना	10	फरैण कलां	3	सुरजभान	सुरजमल				
33	–सम–	–सम–	41	हंसडैहर	8	*गुरजीत सिंह	*सुखतार सिंह	राज सिंह	राम सिंह		
34	–सम–	–सम–	53	कोयल	4	*सलिन्द्र	सलन्द्रि				
35	–सम–	–सम–	57	पीपलथा	4	*गुरभेज सिंह	*गुरमेज सिंह				

पंचकूला :

राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

दिनांक 01 अप्रैल, 2016.

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17, PANCHKULA.

Corrigendum

The 1st April, 2016

No. SEC/E-II/2016/3464.— In continuation of the State Election Commission's notifications mentioned below in column 2 dated 10.02.2016, the following corrigendum is hereby notified:-

Sr No	Notification No.	Name of District/ Block	Sr. No. in the Notifica-tion	Gram Panchayat	Ward No.	Name Sh./Smt./Kumari		Father/ Husband Name		Category	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
						Read as	In place of	Read as	In place of	Read as	In place of
1	SEC/E-II/ 2016/ 2046	Gurgaon/ Gurgaon	9	Dharmpur	06	Rohit	Joginder Singh	Manjeet	Mahaveer Singh		
2	SEC/E-II/ 2016/ 2113	Karnal/ Gharaunda	4	Anchala	02	*Krishan Kumar	* Krishan Lal	Prem Chand	Puran Chand		
3	-do-	-do-	11	Begampur	04	*Sushma	* Susma				
4	-do-	-do-	15	Fazlipur Majra	01	Gulab Singh	Parveen Kumar	Jai Pal	Jagdish Chand		
5	-do-	-do-	18	Garhi Bharal	Sarpanch	Shokin Kumar	Sokin Kumar				
6	-do-	-do-	37	Mubarkabad	02	*Rinku	*Balbinder Singh	Roshan Lal	Surta Ram		
7	-do-	-do-	37	Mubarkabad	03	*Babita	*Rekha Rani	Salinder	Rajbir Singh		
8	-do-	-do-	52	Upli	01			Shishan Singh	Sishan Singh		
9	SEC/E-II/2016/2152	Karnal/ Nilokheri	2	Naraina	02	Dalbir Singh	Johan Lal				
10	-do-	-do-	5	Naraina	05	Sahib Singh	Kuldeep Singh				
11	SEC/E-II/2016/2117	Karnal/Karnal	62	Sohna	03	Deepak	Vikram Kumar	Ram Phal	Balwan Singh		
12	SEC/E-II/2016/2089	Jind/Narwana	10	Frain Kalan	03	Surajbhan	Surajmal				
13	-do-	-do-	16	Amargarh	03	Hukam Chand	Hukam Singh				
14	-do-	-do-	16	Amargarh	08	Bijender	Vijender				
15	-do-	-do-	22	Phulia Khurd	02	*Kavita	*Kabita				
16	-do-	-do-	33	Ambarsar	05	Amit Kumar	Anil Kumar				
17	-do-	-do-	41	Hansdher	08	*Gurjeet Singh	*Sukhtar Singh	Raj Singh	Ram Singh		
18	-do-	-do-	48	Dhanouri	11	Ramniwash	Ramnwash				
19	-do-	-do-	56	Ujahana	07	Vakil Rasila	Vikal Rishala				
20	-do-	-do-	57	Pipaltha	04	*Gurbej Singh	*Gurmej Singh				

Panchkula: State Election Commissioner, Haryana.
The 1st April, 2016.

54217—C.S.—H.G.P., Chd.